भारत सरकार
योजना मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5300
दिनांक 25.03.2026 को उत्तर देने के लिए

नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन (एनएमपी) 2.0

5300. **श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे:**
श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील:
श्री नरेश गणपत म्हस्के:
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:
श्री अतुल गर्ग:
श्रीमती भारती पारधी:
श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर:

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक अवसंरचना परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए वित्तीय वर्ष 2026-2030 की अवधि के लिए नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन (एनएमपी) 2.0 शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) एनएमपी 2.0 के अंतर्गत कुल मुद्रीकरण का लक्ष्य क्या है और विशेषकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों में किन-किन प्रमुख अवसंरचना क्षेत्रों की पहचान की गई है;

(ग) क्या इस कार्यक्रम का उद्देश्य निजी निवेश को आकर्षित करना और परिसंपत्ति उपयोग दक्षता में सुधार करना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) पारदर्शी कार्यान्वयन और निगरानी के लिए स्थापित संस्थागत तंत्र का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अवसंरचना विकास, राजकोषीय स्थिरता और दीर्घकालिक आर्थिक विकास पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय;
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना मंत्रालय एवं
राज्यमंत्री, संस्कृति मंत्रालय

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) और (ख) केंद्रीय बजट 2025-26 ने देश में बुनियादी ढांचे के निर्माण को और तेज करने के लिए 10 लाख करोड़ रुपये वापस लगाने के लिए एनएमपी 2.0 लॉन्च करने की घोषणा की। तदनुसार, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन 2.0 (एनएमपी 2.0) 23 फरवरी, 2026 को लॉन्च की गई थी।

एनएमपी 2.0 ने वित्त वर्ष 2026 से वित्त वर्ष 2030 तक पांच वर्ष की अवधि में केंद्र सरकार की मुख्य परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के माध्यम से 5.8 लाख करोड़ रुपये के निजी क्षेत्र के निवेश सहित कुल 16.72 लाख करोड़ रुपये के मुद्रीकरण की संभावना का अनुमान लगाया है।

मूल्य के हिसाब से वार्षिक चरणबद्धता के संदर्भ में, लगभग 2.49, 3.26, 3.46, 3.68 और 3.81 के सांकेतिक मूल्यों (लाख करोड़ रुपये में) वाली परिसंपत्तियों को क्रमशः वित्त वर्ष 26, वित्त वर्ष 27, वित्त वर्ष 28, वित्त वर्ष 29 और वित्त वर्ष 30 में शुरू किए जाने की परिकल्पना की गई है।

इसमें शामिल क्षेत्र और उनके सांकेतिक परिसंपत्ति मूल्य (लाख करोड़ रुपये में) इस प्रकार हैं: राजमार्ग (मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्क (एमएमएलपी) और रोपवे सहित) – 4.42; रेलवे – 2.62; विद्युत – 2.76; पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस – 0.16; नागर विमानन – 0.27; बंदरगाह – 2.63; भंडारण एवं संग्रहण – 0.10; शहरी – 0.52; कोयला – 2.16; खान – 1.0; दूरसंचार – 0.048; और पर्यटन – 0.012.

एनएमपी 2.0 के तहत मुद्रीकृत की जाने वाली संपत्तियों का विवरण का रखरखाव राज्य-वार आधार पर नहीं किया जाता है।

(ग) से (ङ) परिसंपत्ति मुद्रीकरण से अग्रिम और भविष्य में राजस्व स्रोत उत्पन्न होने की उम्मीद है, जो नए बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अतिरिक्त पूंजी प्रदान करता है। इसके अलावा, एनएमपी में त्वरित बुनियादी ढांचे के विकास को सक्षम करने के लिए 5.8 लाख करोड़ रुपये के निजी क्षेत्र के निवेश वाली परियोजनाएं शामिल हैं। एनएमपी उत्पादक सार्वजनिक संपत्तियों के पुनर्चक्रण को सक्षम बनाता है, जिससे नई परियोजनाओं और पूंजीगत व्यय में पुनर्निवेश के लिए संसाधन खुलते हैं।

एनएमपी के तहत परियोजनाएं संबंधित अनुबंधों द्वारा शासित होती हैं जिनमें मोटे तौर पर सेवाओं की कुशल डिलीवरी और बेहतर परिसंपत्ति उपयोग सुनिश्चित करने के लिए रूपरेखा शामिल होती है।

कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में परिसंपत्ति मुद्रीकरण पर सचिवों का एक प्रमुख समूह परिसंपत्ति मुद्रीकरण कार्यक्रम की प्रगति की निगरानी करता है।

एनएमपी 2.0, पूंजी पुनर्चक्रण को सक्षम करके और निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करके, बुनियादी ढांचे के निर्माण पर उच्च पूंजीगत व्यय का परिणाम प्राप्त होने का अनुमान है जिससे देश की आर्थिक वृद्धि पर प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

*****